

**राजस्थान सरकार**  
**निर्वाचन विभाग**

क्रमांक: एफ 1(17)।।।/बी/निर्वा/2014/पार्ट-I/ 1404

जयपुर, दिनांक : - 13-04-2022

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर कार्यालय हेतु प्रशिक्षित मशीन विद मैन की सेवा दिनांक 31.03.2023 तक उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, जी.एस.टी., आयकर, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कंपनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से खुली निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। विवरण निम्नानुसार है : -

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	बोली प्रतिभूति राशि (रु.)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रु.)	निविदा विक्रय प्रारम्भ	निविदा विक्रय करने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	कम्प्यूटर मय प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विद मैन) (संख्या 02)	2.80 लाख	5600	500/-	13.04.2022	18.04.2022 5:00 बजे	19.04.2022 12:00 बजे	19.04.2022 5:00 बजे

1. निविदा आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के नोटिस बोर्ड व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा प्रतिभूति राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के नाम से बनाना होगा। जिसे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 19.04.2022 को 12:00 बजे तक जमा कराना होगा।
3. वित्तीय निविदा बिड दिनांक 19.04.2022 को 5:00 बजे अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
4. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।



कार्यालयाध्यक्ष एवं  
विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 1(17)।।।/बी/निर्वा/2014/पार्ट-I/ 1404

जयपुर, दिनांक:- 13-04-2022.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, निर्वाचन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर निविदा को प्रकाशित करने की कार्यवाही करावें।
4. नोटिस बोर्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
5. कार्यालय प्रति।



कार्यालयाध्यक्ष एवं  
विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर





## राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग

### निविदा पत्र की मुख्य शर्तें

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि सम्पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बावत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी भुगतान करने का दायित्व संबंधी संवेदक/बोलीदाता का होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर से श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ., ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
8. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदाओं, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु हैल्पलाईन नं. एवं संवेदक/बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
10. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने का प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

५५



12. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिए समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को DEBAR कराने की कार्यवाही की जायेगी।
16. प्रशिक्षित मैन पावर कार्मिकों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा। प्रशिक्षित मैन पावर कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर प्रशिक्षित मैन पावर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
17. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तरण पर संविदा की जा सकती है।
18. अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर प्रशिक्षित मैन पावर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन प्रशिक्षित कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
19. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन प्रशिक्षित कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गई हो।
20. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
21. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा, या भाडे (सब-लेट) पर नहीं देगा।
22. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी। वह कार्यादेश जारी होने के 3 दिवस में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
23. मूल्यांकन की कसौटी :- तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाईड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
24. बोलियों का अपवर्जन:- अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
25. बोली की प्रतिभूति राशि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के नाम पर डिमाण्ड ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक/E-Grass के रूप में जमा कराई जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।

बोली प्रतिभूति का समपहरण ( )

बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा :-

५२



- a) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
- b) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
- c) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- d) जब सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में प्रशिक्षित कार्मिक कार्य प्रारम्भ नहीं करता।
- e) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

26. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :-

- a) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज.जयपुर के नाम पर जमा करानी होगी। सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
- b) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
- c) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

27. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण ( Forfeiture of work performance Security Deposit ) :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

- a. जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- b. जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- c. जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्ताई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

28. भुगतान :- (1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 07 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

29. परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages ) :- परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपूर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिये की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:-

- a) विहित सेवा/कार्य अवधि को एक चौथाई अवधि के लिये - 2.5%
- b) विहित सेवा/कार्य अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक-5% किन्तु विहित अवधि से आधी अवधि अनधिक के लिए।
- c) विहित सेवा/कार्य अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए-7.5% किन्तु तीन चौथाई अनधिक अवधि के लिये।
- d) विहित सेवा/कार्य अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए - 10%
- e) विलम्बन की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।
- f) परिनिर्धारित अधिकतम राशि 10% होगी।
- g) यदि बोलीदाता किन्हीं कारणों के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरी करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

5

h) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सेवा की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति या रहित की जा सकेगी।

30. निविदा प्रपत्र पर संवेदक/संस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलग्न करे।

31. आर.टी.टी.पी. एक्ट, 2012, नियम, 2013 एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 एवं 14.11.2018 के प्रावधान लागू होंगे।

32. बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता है :- संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर, फोन नं. 2227174

E-mail : fa.election@gmail.com

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
नाम मय सील

Q

ह



**निर्वाचन विभाग के लिये कम्प्यूटर मशीन मय ऑपरेटर की सेवाएँ सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुबन्ध पर लेने के सम्बन्ध में मुख्य शर्तें-**

1. विभाग को उपलब्ध कराये जाने वाली कम्प्यूटर मशीन का स्पेसिफिकेशन/कन्फिगरेशन निम्नानुसार अथवा उससे उच्च स्तर का होना चाहिए:-

**Machine Specifications:**

A. **Computer** - Intel Core i3 /Equivalent AMD based Computer or Higher speed RAM 2/4 GB LAN card CD/DVD Writer, Standard keyboard optical mouse, standard serial, parallel and USB Port, windows 7 or higher, Anti Virus Preinstalled M.S office, Responsibility of software license will be borne by the Contractor.

B. **Printer** - Black and White laser printer with speed 15 ppm speed or more. For specific needs dot-matrix/ inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

C. **UPS** - Online/ Office UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.

2. कम्प्यूटर ऑपरेटर के सम्बन्ध में निम्नानुसार योग्यता एवं ज्ञान का पूर्ण होना आवश्यक है:-

**Manpower** - The personal should have knowledge to operate computer in window / Linux environment , good Knowledge/ practice in word Processor, spread sheet and Internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing Hindi and English.

3. फर्म द्वारा उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटर यदि खराब हो जाता है तो उसके स्थान पर शीघ्र ही दूसरा कम्प्यूटर तुरन्त कराया जायेगा। साथ ही यदि लगाए जाने वाला ऑपरेटर अवकाश पर रहेगा तो उसके स्थान पर दूसरा ऑपरेटर उपलब्ध कराना होगा। यदि कम्प्यूटर खराब होने की स्थिति में दूसरा कम्प्यूटर तुरन्त उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथवा ऑपरेटर के अवकाश पर रहने पर दूसरा ऑपरेटर शीघ्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विभाग द्वारा दी जाने वाली प्रति माह की राशि मेंसे अनुपातिक राशि (स्वीकृति दर संविदा) की कटौती करके भुगतान किया जावेगा। तथा रुपये 250/- प्रतिदिन /प्रतिव्यक्ति शास्ति आरोपित की जावेगी।

4. सामान्यता समस्त राजपत्रित अवकाश ( राजस्थान सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए घोषित ) पर सेवा प्रदाता के कार्मिक का भी अवकाश रहेगा किन्तु विशेष परिस्थिति में सक्षम/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा लिखित में राजपत्रित अवकाश अथवा कार्यालय समय पश्चात आकर/रुककर कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऑपरेटरो को आदेश की पालना करनी होगी। इस हेतु अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

5. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये ऑपरेटर के चरित्र एवं ईमानदारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी। यदि ऑपरेटर का कार्य सन्तोषप्रद नहीं होती है अथवा अन्य कोई शिकायती होती है तो उसे बदलने की सूचना देने के 24 घण्टे में ऑपरेटर को बदलना होगा।

6. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जावेगी उसे निर्धारित प्रारूप में लिखित अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध भंग करने की दशा में बोलीदाता की अमानत राशि जब्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

7. कम्प्यूटर सेवाएँ देने के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. कम्प्यूटर सिस्टम सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारण, रखरखाव आदि रखने की पूरा जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विधिक कार्यवाही क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय होगा।

10. बोली के सम्बन्ध में विभाग द्वारा लिये गये निर्णय अन्तिम एवं मान्य होंगे।

11. स्टेशनरी,सी. डी. एवं फ्लॉपी कन्ज्यूमेबल्स आदि आवश्यकतनुसार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी तथा जो विभाग की सम्पत्ति रहेगी। परन्तु प्रिन्टर्स में नया टोनर/ नया रिबन प्रथम बार बोलीदाता द्वारा ही उपलब्ध कराना होगा।

12. Rajasthan Transparency in Public procurement Act. 2012 and Rajasthan Transparency in public procurement rules, 2013 and GF&AR के समस्त प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय जारी किये जाने वाले दिशा निर्देशो/आदेशो, जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो, निर्वाचन विभाग राजस्थान, जयपुर एवं बोलीदाता द्वारा मान्य होंगे।

मुझे/ हमें उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं मोहर



**राजस्थान सरकार**  
**निर्वाचन विभाग**

**तकनीकी बिन्दु**

1. निविदा जारी करने की अंतिम दिनांक व समय
  2. बोलीदाता/संवेदक का नाम : .....
  3. डाक का पता : .....
  4. फोन/मोबाईल नं. : .....
  5. ई-मेल : .....
  6. बैंक का नाम : ..... IFSC Code .....
- खाता संख्या .....
7. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित आवश्यक पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जायेगा तथा निम्न पंजीकरण प्रमाण पत्रों के स्व-हस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी, दस्तावेज प्रति संलग्न है :

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	GST				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	जुलाई-2021 की स्वप्रमाणित जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति				
8	बोली प्रतिभूति राशि रुपये 11,20/- का प्रमाण				
9	बोली प्रपत्र शुल्क की राशि रुपये 500/- का प्रमाण				

8. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 3 वित्तीय वर्ष (2018-19, 2019-20 व 2020-21) में न्यूनतम टर्नओवर रुपये 10.00 लाख एवं किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम टर्नओवर 5 लाख रुपये होना चाहिए। जिसके समर्थन में सी.ए.का प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन नं. व सील सहित) की प्रति संलग्नक करवाना आवश्यक है।
9. निविदा बन्द लिफाफे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के नाम के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र को दिनांक 19.04.2022 को 12:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
10. प्रतिभूति/निविदा प्रपत्र शुल्क, राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर (Receipt की & Payment की) के पक्ष में बनाना होगा। निविदा पत्र मय प्रतिभूति/निविदा प्रपत्र शुल्क, राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक को दिनांक 19.04.2022 को 12:00 बजे तक जमा करना आवश्यक है।
11. मैं/हम निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गयी उक्त निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
12. संवेदक/बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली/प्राईस बिड को छोड़कर शेष बोली दस्तावेजों को बोलीदाता के सम्बन्धित प्रमाण पत्र व कागजात के साथ बोली के साथ स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। पूर्ण हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज इस बात का प्रमाण होगा कि बोलीदाता बोली दस्तावेज में अंकित सभी शर्तों को स्वीकार करता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
नाम मय सील

✓

राजस्थान सरकार  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर  
वित्तीय बोली/प्राईस बिड

कार्य आधारित पर सेवाओं के उपापन के लिए वित्तीय बोली/प्राईस बिड दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी :-

संवेदक का नाम :- .....

पता :- .....

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगा मय संख्या				EPF दर प्रतिशत एवं राशि 12%	ESI दर प्रतिशत एवं राशि (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति माह प्रति ईकाई रु.)	कुल राशि रु.
		श्रमिकों की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी की दर (प्रति माह प्रति ईकाई रु.)	श्रमिकों की संख्या	राशि (प्रति माह प्रति ईकाई रु.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रशिक्षित मशीन विद मैन (संख्या 2)	उच्च कुशल	8476	02					

उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ सं. 1 से 5 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है। केवल स्तम्भ 6 से 10 तक बोलीदाता द्वारा प्रविष्टि की जावेगी।

आपूर्ति किये जाने वाले प्रशिक्षित मैन पावर कार्मिक की संख्या में विभाग की आवश्यकता अनुसार कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

GST राशि अतिरिक्त रु. से देय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
नाम मय सील

५२



## घोषणा पत्र

निविदा की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण /प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है। तथा अधिनियम की धारा 46 एवं नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित(Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर पतिकूल प्रभाव डालें बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/ एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
नाम मय सील



**Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest**

*Handwritten mark*

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
  - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
  - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
  - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

*Handwritten* date

*Handwritten mark*

signature of bidder



**DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING**

**QUALIFICATIONS.**

**DECLARATION BY THE BIDDER**

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated ..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, That:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/W have fulfilled my / our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any Local Authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of Legal Proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers do not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Signature of Bidder

Name :

Designation

Address

Date :

Place :

*de, ✓*



**MEMORANDUM OF APPEAL UNDER THE  
RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC  
PROCUREMENT ACT, 2012**

**Appal No. .... of .....**

**Before the ..... (First/Second Appellate  
Authority)**

- (1) **PARTICULARS OF APPELLANT:**
  - (i) **Name of the Appellant:**
  - (ii) **Official address, if any:**
  - (iii) **Residential address :**
- (2) **Name and address of the respondent(s):**
  - (i)
  - (ii)
  - (iii)
- (3) **Number and date of the order appeal against and Name and Designation of the officer / authority who passed of the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or ommission of the Procuring Entity in contravention of the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:**
- (4) **If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:**
- (5) **Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :**

*Handwritten mark: a checkmark with a flourish.*

*Handwritten mark: a circled number 2.*



Date :

Place :

Address

Name :

Appellant's Signature

.....

7 Payer : .....

..... (Supported by an affidavit)

.....

6 Ground of Appeal: .....



## Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is \_\_\_\_\_

The designation and address of the Second Appellate Authority is \_\_\_\_\_

### (1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

### (4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.
- 2, ✓



**(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

**(6) Fee for filing appeal**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

2

2 ✓

date

signature of bidder



## Annexure D : Additional Conditions of Contract

### 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

### 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

### 3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of

dv



FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ..... of .....

Before the ..... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....  
.....

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....  
.....

Place .....

Date .....

Appellant's Signature

*de v*

